

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक उपक्रम/निगम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2019

विषय:- राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कर्मिकों को वर्ष 2018-19 के लिये 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या-352/XXVII(7)-I(1)/2003, दिनांक 21, अक्टूबर 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस की स्वीकृति अनुमन्य करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-101/VII-I/2018-233(उद्योग)/2008, दिनांक 14.02.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/निकाय/सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए अपने कर्मिकों हेतु तदर्थ बोनस की स्वीकृति निर्गत/अनुमन्य किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 565 (1)/VII-I/2019-233(उद्योग)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 31.10.2018 के क्रम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव।